अति तत्काल

फाइल संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 31 जनवरी, 2020

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए दिसम्बर, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **दिसम्बर, 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

आलोक
31.01.2020

(आलोक कुमार वर्मा)
निदेशक (पी0 एण्ड सी0)
दूरभाष नं0 2307 1149

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उपराष्ट्रपति के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

उपभोक्ता मामले विभाग के दिसम्बर, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक :-

1.1 प्याज की कीमतों की निरंतर वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 5 और 12 दिसम्बर, 2019 को माननीय मंत्रियों की समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया था जिनमें समिति को प्याज, दालों और खाद्य तिलहनों के मौजूदा परिदृश्यों के बारे में सूचित किया गया। समिति को माननीय मंत्रियों की समिति के निर्णय के अनुसरण में किए गए आयात की स्थिति से भी अवगत कराया गया।

1.2 एमएमटीसी ने प्याज के आयात के लिए 6 टेंडर और घरेलू व्यापारियों से आयातित प्याज की खरीद के लिए 2 टेंडर आमंत्रित किए। दो टेंडरों को अंतिम रूप दिया गया और प्याज के आयात की निवल मात्रा को लगभग 36,500 मीट्रिक टन करते हुए एमएमटीसी द्वारा लगभग 25,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात के लिए एलओआई जारी किया गया। बंदरगाह पर 2028 मीट्रिक टन आयातित प्याज की आवक हुई और इसे दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना आदि के लिए प्रेषित कर दिया गया। प्याज की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, मदर डेयरी और नेफेड को आयातित प्याज को लागत आधार पर खुदरा बिक्री का परामर्श दिया गया। प्याज के परिदृश्यों के साथ-साथ माह के दौरान प्याज के आयात और बिक्री की पुनरीक्षा के लिए पुनर्गठित पीएसएफ प्रबंधन समिति की अनेक बैठकें आयोजित की गई।

1.3 माननीय मंत्री जी और सचिव द्वारा राज्यों को पत्र भेजे गए जिनमें राज्यों से आयातित प्याज की उनकी आवश्यकताओं की पुष्टि करने और प्याज की कीमत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समुचित उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया। राज्यों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए उनके साथ वीडियो-कांफ्रेंसों का आयोजन भी किया गया। शुरूआत में, राज्यों ने लगभग 33,500 मीट्रिक टन प्याज की आवश्यकताएं दर्शाई तथापि चूंकि दिसम्बर माह के अंत में कीमतें कम होने लगी, अतः राज्यों ने अपनी मांग वापिस ले लीं।

1.4 उपभोक्ता मामले विभाग ने लगभग 15.64 लाख मीट्रिक टन दालों के बफर का सृजन किया है। जो राज्य अपनी कल्याणकारी स्कीमों में दालों के उपयोग के लिए डीआरपी/बाजार आधारित कीमतों पर दालों की बिक्री के लिए पात्र हैं, उनको इस बफर से 8.17 लाख मीट्रिक टन दालों की पेशकश की गई। इसके अलावा, तूर की नीलामी की गई और बढ़ते मूल्य रूझानो को नियंत्रित करने के लिए बाजार में 0.97 लाख मीट्रिक टन का निपटान किया गया।

1.5 कीमतों, दालों एवं प्याज के बफर के प्रबंधन के साथ-साथ उचित दरों पर उनकी उपलब्धता में सुधार के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों एवं एजेंसियों को उनकी रिलीज की पुनरीक्षा के लिए साप्ताहिक बैठकों का आयोजन किया गया। प्याज, दालों की खुदरा बिक्री की स्थिति, प्याज पर स्टॉक सीमा के प्रवर्तन और संबंधित मामलों की पुनरीक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ वीडियो कांफ्रेंसों का आयोजन भी किया गया।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम:

2.1 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्याज पर लगाई गई स्टॉक सीमा को संशोधित करके कम करते हुए थोक विक्रेताओं के मामले में 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के मामले में 2 मीट्रिक टन कर दिया गया। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उक्त स्टॉक सीमाओं के सख्त प्रवर्तन और बेईमान व्यापारियों के विरूद्ध संगठित छापेमारी के जरिए जमाखोरी-रोधी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

3. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ):

3.1 एनसीसीएफ के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित अंतरिम बोर्ड, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 2 सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी शामिल हैं, बोर्ड के कार्यकरण का संचालन कर रहा है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव को प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से एनसीसीएफ के लिए एक नियमित प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. <u>भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) :-</u>

4.1 आईएस 10500:2012 के अनुसार पाइप पेय जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में बी.आई.एस. द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को मानक भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) द्वारा किया गया और इसमें जल आपूर्ति और पीएचई विभागों को प्रतिनिधित्व करते हुए 23 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। बी.आई.एस. के अधिकारियों द्वारा आईएस 10500 – पेयजल संबंधी विनिर्देशन और आईएस 15000 – जोखिम विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

4.2 बी.आई.एस. (वैज्ञानिक संवर्ग में भर्ती) विनियम, 2019 को दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

5. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस:

5.1 दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से "भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019" विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता

दिवस, 2019 मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) द्वारा किया गया। इस अवसर पर, माननीय राज्य मंत्री जी ने स्कूली छात्रों, आईआईपीए द्वारा आयोजित पोस्टर मेकिंग कम्पटीशन के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाणपत्रों का वितरण किया। माननीय मंत्री जी द्वारा सीसीएस, आईआईपीए के पांच प्रकाशनों को भी रिलीज किया गया।

6. मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		दिसम्बर, 2019 (अनन्तिम)	नवंबर, 2019 (अनन्तिम)	दिसम्बर, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक # **(वार्षिक)**	2.59	0.58	3.46
2	थोक मूल्य सूचकांक # **(खाद्य वस्तुएं)**	13.24	11.08	-0.42
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	8.61	7.62	4.86
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) **(संयुक्त)***	7.35	5.54	2.11
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)***	14.12	10.01	-2.65

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

7. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य जुलाई, माह की तुलना में नवंबर, 2019 माह की तुलना में दिसम्बर, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य नवंबर, 2019 की तुलना में दिसम्बर, 2019 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -:

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें (रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	दिसम्बर, 2019 (अद्यतन)	नवंबर, 2019 (विगत माह)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	33	34	-1
2	गेहूं	28	28	0
3	आटा	30	30	0
4	चना दाल	67	67	0
5	तूर दाल	88	88	0
6	उड़द दाल	96	91	5
7	मूंग दाल	90	88	2
8	मसूर दाल	65	65	0
9	चीनी	39	40	-1
10	दूध (प्रति लीटर)	45	45	0
11	मूंगफली का तेल	136	135	1
12	सरसों का तेल	114	113	1
13	वनस्पति	83	81	2
14	सोया तेल	94	93	1
15	सूरजमुखी का तेल	102	102	0
16	पाम ऑयल	82	78	4
17	गुड़	46	47	-1
18	खुली चाय	217	217	0
19	पैकबंद नमक	16	16	0
20	आलू	25	23	2
21	प्याज़	95	61	34
22	टमाटर	29	38	-9

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृति' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापित नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. **ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति**

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
190	**148**

6. **लोक शिकायतों की स्थिति** :

दिसम्बर, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**दिसम्बर, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
1190	**481**

7 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

दिसम्बर, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**दिसम्बर, 2019** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
59076	**45673**

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 114 केन्द्रों से 22 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

*****